पर्यावरण और हम

यह एडिटोरियल 08/06/2022 को 'हिंदुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित ''Climate and Us | A movement that puts a spotlight on West's wasteful consumption'' लेख पर आधारित है। इसमें पश्चिमी देशों के अपव्ययी उपभोग को उजागर करने के लिये और जलवायु परिवर्तन से संबंधित भारत की समस्याओं के समाधान के लिये भारत द्वारा की गई एक विशेष पहल के बारे में चर्चा की गई है।

संदर्भ

हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 'पर्यावरण के लिये जीवनशैली आंदोलन' [Lifestyle for the Environment (LiFE) Movement] वैश्विक पहल लॉन्च की गई। यह आंदोलन विकसित और विकासशील देशों के उपभोग पैटर्न के साथ ही जलवायु परिवर्तन से संबंधित ऐतिहासिक ज़िम्मेदारी, प्रति व्यक्ति CO_2 उत्सर्जन और कार्बन स्पेस जैसे पहलुओं को वैश्विक ध्यान के केंद्र में लाने का एक प्रयास है।

वैश्विक जीवनशैली आंदोलन के उद्देश्य क्या हैं?

- यह पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवनशैली पर शिक्षाविदों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों से विचारों एवं सुझावों को आमंत्रित करने के लिये एक वैश्विक आह्वान की शुरुआत करेगा और इस क्रम में व्यक्तियों, समुदायों और संगठनों को जीने के तरीके में रूपांतरण के लिये प्रेरित करेगा।
- इनमें जल, परिवहन, आहार, बिजली, पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के संबंध में व्यक्तियों, घरों और समुदायों पर लक्षित व्यवहार-परिवर्तन समाधान भी शामिल हैं।
- यह जलवायु संकट के संबंध में स्थानीय सामाजिक समाधानों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये सोशल मीडिया नेटवर्क की शक्ति का लाभ उठाएगा।
- ऐसे नवोन्मेषी समाधानों पर भी विचार आमंत्रित किए जाएँगे जो पारंपरिक, जलवायु-अनुकूल अभ्यासों को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देते हैं और/या उन समुदायों के लिये आजीविका विकल्प का निर्माण करते हैं जो जलवायु-अनुकूल उत्पादन की ओर संक्रमण के साथ अपनी आजीविका खोने का खतरा रखते हैं।
- किसी भी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और/या स्थानीय सर्वोत्तम अभ्यासों का पालन करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिन्हें जलवायु कार्रवाई से संबंधित व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित करने के लिये व्यावहारिक रूप से संवर्द्धित किया जा सकता है।

हमें इस प्रकार के आंदोलन की आवश्यकता क्यों है?

- COP26 ग्लासगो जलवायु सम्मेलन के ग्लासगो संधि के प्रारूपण के दौरान विकसित और विकासशील देशों के बीच निम्नलिखित कुछ विषयों पर संघर्ष की स्थिति बनी थी-
  - **ऐतिहासिक उत्तरदायित्व:** यह औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के बाद से विकसित विश्व द्वारा किये गए ऐतिहासिक उत्सर्जन को संबोधित करने का प्रयास करता है,
  - **कार्बन उपनिवेशवाद:** 'समान विचारधारा वाले विकासशील देश' (LMDC)—जिसमें भारत और चीन भी शामिल हैं, के अनुसार विकसित देश 'कार्बन उपनिवेशवाद' (Carbon Colonialism) का प्रदर्शन कर रहे हैं।
    - इसका आशय यह है कि जलवायु परिवर्तन के प्रति 'साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्व' (Common But Differentiated Responsibility- CBDR) के सिद्धांत का पालन करने के बजाय विकसित देश विकासशील देशों पर तत्काल शुद्ध-शून्य लक्ष्यों की घोषणा करने का दबाव डाल रहे हैं अथवा 1.5 डिग्री वैश्विक तापमान लक्ष्य प्राप्ति के संबंध में अपने पक्ष में झुकी वार्ता को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि विश्व के एक बड़े हिस्से की विकासगत आवश्यकताओं की पूरी तरह से उपेक्षा कर रहे हैं।
  - हाल ही में स्टॉकहोम +50 सम्मेलन (जो ऐतिहासिक स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था) में प्रमुख अनुशंसाओं के वक्तव्य में भी उपभोग और अपव्ययी दोहन के महत्त्वपूर्ण विषय पर कुछ भी नहीं कहा गया।
    - इसके कारण, ऐतिहासिक उपभोग पैटर्न के प्रति जवाबदेही का अभाव है।

CBDR क्या है?

- 'साझा कति विभिदति उत्तरदायत्वि' (कभी-कभी 'और संबंधति क्षमताओं' वाक्यांश के साथ) अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक सद्धिांत है जसिका आशय है कविभिन्नि देशों के पास जलवायु परविर्तन जैसे सीमा-पारीय पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधति करने की अलग-अलग क्षमताएँ और उत्तरदायत्वि हैं। यह सद्धिांत नम्निलखिति दो आवश्यकताओं में संतुलन का प्रयास करता है:
    - पर्यावरणीय वनिाश और इसके शमन के लयि सभी राज्यों द्वारा व्यक्तगित उत्तरदायत्वि ग्रहण करने की आवश्यकता; और
    - यह चह्नित करने की आवश्यकता कसिमस्या के लयि सभी राज्य एकसमान रूप से ज़म्मिदार नहीं हैं, न ही कार्रवाई में एकसमान रूप से सक्षम हैं।

अनुलग्नक-1 और गैर-अनुलग्नक-1 देश

- अनुलग्नक-1 पक्षकारों में वे औद्योगकि देश शामलि हैं जो वर्ष 1992 में 'आर्थकि सहयोग और वकिास संगठन' (OECD) के सदस्य थे और वे देश जो EIT (Economies in Transition) पक्षकार थे। इनमें रूसी संघ, वभिन्नि बाल्टकि राज्य और वभिन्नि मध्य एवं पूर्वी यूरोपीय राज्य शामलि हैं।
- गैर-अनुलग्नक-1 पक्षकार अधकिांशतः वकिासशील देश हैं। वकिासशील देशों के कुछ समूहों को वशिष रूप से जलवायु परविर्तन के प्रतकिूल प्रभावों के प्रतसिंवेदनशील माना गया है, जनिमें नचिले तटीय क्षेत्रों वाले देश और मरुस्थलीकरण एवं सूखा-प्रवण देश शामलि हैं।
- अन्य अल्पवकिसति देश (LDC), जो जीवाश्म ईंधन उत्पादन और वाणज्यि से प्राप्त आय पर अत्यधकि नर्भिर हैं, जलवायु परविर्तन प्रतक्रियिा उपायों के संभावति आर्थकि प्रभावों के प्रतअिधकि भेद्यता रखते हैं। जलवायु परविर्तन कन्वेंशन उन गतविधियिों पर बल देता है जो इन संवेदनशील देशों की वशिष आवश्यकताओं और चतिाओं के समाधान का वादा करती हैं, जैसे नविेश, बीमा और प्रौद्योगकिी हस्तांतरण।

भारत द्वारा उजागर की गई वभिन्नि असमानताएँ

- प्रतवि्यक्तउित्सर्जन और संसाधन उपभोग में व्यापक अंतर है।
- 'क्लाइमेट इक्वटिी मॉनटिर' (जलवायु कार्रवाई में इक्वटिी का आकलन करने के लयि एक ऑनलाइन डैशबोर्ड) के अनुसार वभिन्नि देशों का प्रतवि्यक्तउित्सर्जन इस प्रकार है-
    - ऑस्ट्रेलयिा – प्रतवि्यक्त22tco2eq (tonne of CO2 equivalent) या CO2 उत्सर्जन प्रतवि्यक्तमिीट्रकि टन
    - संयुक्त राज्य अमेरकिा - 20.2 tco2eq प्रतवि्यक्ति
    - भारत - 2.4 tco2eq प्रतवि्यक्ति
    - ब्राज़ील - 5.3 tco2eq प्रतवि्यक्ति
- वभिन्नि देशों के प्रतवि्यक्तसिंसाधन उपभोग से यह भी पता चलता है ककिवर्ष 2019 में अमेरकिा और अन्य वकिसति देशों में प्रतवि्यक्ति बजिली की खपत सबसे अधकि थी।
- क्लाइमेट इक्वटिी मॉनटिर द्वारा वैश्वकि कार्बन बजट का एक इंटरेक्टवि मैपगि भी प्रस्तुत कयिा गया है जसिमें वभिन्नि देशों द्वारा वैश्वकि बजट में अब तक उपयोग कयि जा चुके उनके हस्सि के अनुरूप उनका वर्गीकरण कयिा गया है।
- यह दर्शाता है कअिधकिांश अनुलग्नक-1 देशों ने अपने उचति हस्सि से अधकि का उपभोग कर लयिा है और ऋण में हैं जबकगिैर-अनुलग्नक 1 देशों ने अभी तक अपने हस्सि का उपभोग नहीं कयिा है और क्रेडटि की स्थतिि रखते हैं।
- यह वकिसति देशों में नर्णिय लेने की कमी या कार्रवाई करने की अनचि्छा और नीतगितहीनता की स्थतिकिी पुष्टकिरता है।

आगे की राह

- नीतआियोग तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परविर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की देखरेख में कार्यान्वति LiFE आंदोलन को वैश्वकि स्तर पर भागीदारी और समर्थन प्राप्त हो रहा है। नीतआियोग ने संयुक्त राष्ट्र, वशि्व संसाधन संस्थान (WRI), सेंटर फॉर सोशल एंड बहिवियर चेंज (CSBC) और बलि एंड मेलडिा गेट्स फाउंडेशन (BMGF) की भागीदारी के साथ वभिन्नि अनुसंधान क्षेत्रों के लयि दुनयिा भर से वचिार आमंत्रति कयि हैं।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस पहल की वर्चुअल लॉन्चगि के अवसर पर बलि गेट्स (बलि एंड मलिडिा गेट्स फाउंडेशन के सह-अध्यक्ष), लॉर्ड नकिोलस स्टर्न (ग्रांथम रसिर्च इंसटीट्यूट के अध्यक्ष), प्रो. कैस सनस्टीन (हार्वर्ड में रॉबर्ट वाल्मसली वशि्ववदि्यालय के प्राध्यापक), इंगर एंडरसन (UNEP के वशि्व प्रमुख); डेवडि मलपास (वशि्व बैंक के अध्यक्ष) जैसे गणमान्य लोग उपस्थति थे जो व्यक्तयिों के साथ ही वभिन्नि समुदायों एवं समाजों पर एक बड़ा प्रभाव रखते हैं और नशि्चय ही इससे लोगों से संलग्नता बढ़ाने में मदद मलिेगी।
- असमानताओं को उजागर करने और नवोन्मेषी समाधानों के साथ बदलाव लाने की ज़रूरत है।
- यह आंदोलन भारत के अंदर असमानताओं को उजागर करने और उन्हें संबोधति करने का भी एक अवसर प्रदान कर सकता है
    - सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के एक अध्ययन के अनुसार 71 प्रतशित भारतीय स्वस्थ आहार ग्रहण कर सकने का सामर्थ्य नहीं रखते।
    - इसके अनुसार एक औसत भारतीय व्यक्तकि आहार में पर्याप्त फल, सब्जयिाँ, फलयिाँ, मेवे और साबुत अनाज का अभाव होता है;
    - देश के अधकिांश भागों में स्वच्छ जल और पर्यावरण तक पहुँच का भी संकट मौजूद है।
- भारत में लाखों गरीब लोगों की सेहत और आजीवकिा को संबोधति करने की आवश्यकता है।
- कोयले पर नर्भिर राज्यों के उपयुक्त संक्रमण पर भी ध्यान दयिा जाना चाहयि, जो जल्द ही उद्योग और नौकरयिों में एक बड़े संक्रमण से गुज़र सकते हैं।

अभ्यास प्रश्न: ''भारत के नेतृत्व में शुरू हुए वैश्वकि जीवनशैली आंदोलन द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रकाश डालें और आपके अनुसार इन समस्याओं के क्या समाधान हो सकते हैं?

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/climate-and-us